मध्यम वर्ग की कहानी

निरंतर प्रगति और सहयोगी शासन

5 जून, 2025

परिचय

एक दशक से भी अधिक समय से, भारत के मध्यम वर्ग ने खुद को राष्ट्र की प्रगति की कहानी के केंद्र में पाया है। उनकी आशाओं, जरूरतों और आकांक्षाओं को न केवल सुना गया है, बल्कि उद्देश्यपूर्ण तरीके से उन पर काम भी किया गया है। कर राहत से लेकर उनके हाथों में अधिक पैसा आने तक, पेंशन योजनाओं से लेकर बुढ़ापे में सुरक्षा का वादा करने तक, पिछले ग्यारह वर्षों में लाखों लोगों के जीवन को आसान, निष्पक्ष और अधिक सम्मानजनक बनाने के लिए लगातार और ईमानदार प्रयास किए गए हैं।

सरकार ने लालफीताशाही को खत्म किया है, नियमों को सरल बनाया है और रोजमर्रा की व्यवस्थाओं को बेहतर बनाया है। चाहे टैक्स दाखिल करना हो, घर खरीदना हो, काम पर आना-जाना हो या दवाइयों का खर्च उठाना हो, चीजें सरल और अधिक सुलभ हो गई हैं। ये बिखरे हुए बदलाव नहीं हैं, बल्कि सुधारों का एक पैटर्न है जो आम नागरिकों की वास्तविक चिंताओं को दर्शाता है। इसमें विशेष बात है निरंतरता। साल दर साल, बजट दर बजट, कदम दर कदम, सरकार मध्यम वर्ग के साथ खड़ी रही है। ऐसा करके, उसने न केवल उनकी

कड़ी मेहनत का सम्मान किया है, बल्कि उन्हें भारत के विकास के प्रमुख चालकों के रूप में भी मान्यता भी दी है।

सरल कर और सुनिश्चित पेंशन

पिछले ग्यारह वर्षों में, सरकार ने मध्यम वर्ग के जीवन में वास्तविक बदलाव लाने के लिए प्रतीकात्मक उपायों से आगे बढ़कर काम किया है। आयकर दरों को कम करने से लेकर रिटर्न को सरल बनाने तक, हर कदम नागरिकों को उनकी कमाई का ज़्यादा हिस्सा रखने देने के मूल विचार के साथ जुड़ा हुआ है।

दृष्टिकोण स्पष्ट है। नागरिकों की बात सुनें, सिस्टम को सरल बनाएं और अपने वादों को पूरा करें।

सबसे हालिया कर सुधार, विशेष रूप से केंद्रीय बजट 2025-26 में किए गए सुधार, इस बात का स्पष्ट संकेत हैं कि सरकार ने राष्ट्रीय विकास के स्तंभ के रूप में मध्यम वर्ग पर अपना भरोसा रखा है। चाहे वह शून्य कर के लिए आय सीमा बढ़ाना हो, सरल कर व्यवस्था शुरू करना हो या रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया पहले से कहीं ज़्यादा आसान बनाना हो, प्रयास निरंतर और केंद्रित रहे हैं। जो बात सबसे अलग है, वह सिर्फ़ सुधारों का पैमाना नहीं है, बल्कि ईमानदार, मेहनती करदाताओं के लिए निष्पक्षता और मान्यता की भावना है।

> त्वरित तथ्य:
>
> 12.75 लाख रुपये तक की आय पर शून्य कर, करोड़ों लोगों को लाभ।
>
> 11 वर्षों में रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या 3.91 करोड़ से बढ़कर 9.19 करोड़ हो गई।
>
> 2015-16 और 2024-25 के बीच मुद्रास्फीति औसतन 5% रही, जो 2004-05 से 2013-14 के दौरान 8.2% थी।

<u>आसान आयकर अनुपालन</u>

पिछले ग्यारह वर्षों में, आयकर नीति ने लगातार सार्थक राहत प्रदान की है। सरकार ने छूट की सीमा बढ़ाई, मानक कटौती शुरू की, 2020 में सरलीकृत कर व्यवस्था शुरू की और कागजी कार्रवाई कम की। इन प्रयासों से करदाताओं का जीवन आसान हुआ है।

New Income Tax Slab Structure

Total Income Per Annum	Rate of Tax
₹0-4 Lakh	NIL
₹4-8 Lakh	5%
₹8-12 Lakh	10%
₹12-16 Lakh	15%
₹16-20 Lakh	20%
₹20-24 Lakh	25%
Above ₹24 Lakh	30%

*Salaried individuals earning upto ₹ 12.75 Lakh per annum will pay NIL tax, due to standard deduction of ₹ 75,000.

केंद्रीय बजट 2025-26 में एक और बड़े बदलाव की घोषणा की गई। सालाना 12 लाख रुपये तक कमाने वाले व्यक्ति अब पूंजीगत लाभ जैसी विशेष आय को छोड़कर कोई आयकर नहीं देंगे। 75,000 रुपये की मानक कटौती के साथ, 12.75 लाख रुपये कमाने वाले भी कोई कर नहीं देंगे। मानक कटौती स्वचालित रूप से कर योग्य आय को

एक निश्चित राशि से कम कर देती है, जिससे वेतनभोगी कर्मचारियों पर बोझ कम हो जाता है क्योंकि इससे उन्हें कई छूटों का दावा करने या विस्तृत प्रमाण प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होती है। इस सुधार से करोड़ों वेतनभोगी नागरिकों को लाभ होगा। सरकार द्वारा लगभग 1 लाख करोड़ रुपये राजस्व देने के बावजूद आया यह सुधार मध्यम वर्ग की जरूरतों की गहरी समझ को दर्शाता है । आयकर रिटर्न सरलीकरण, कर अनुपालन को आसान बनाने के लिए, व्यक्तिगत करदाताओं को अब पहले से भरे हुए आयकर रिटर्न प्रदान किए जाते हैं। इन रिटर्न में वेतन आय, बैंक ब्याज, लाभांश और बहुत कुछ जैसे विवरण शामिल होते हैं।

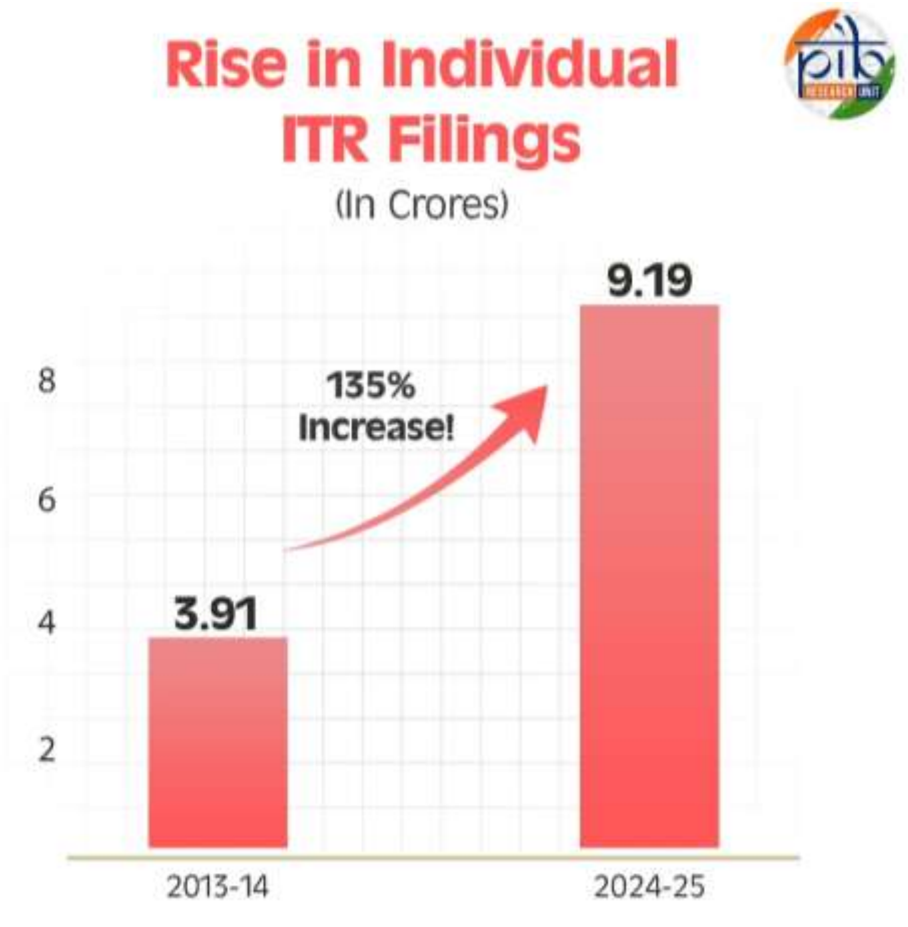

यह सहजता व्यक्तिगत रिटर्न फाइलिंग के वृद्धि में परिलक्षित होती है, जो वित्त वर्ष 2013-14 में 3.91 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2024-25 में 9.19 करोड़ रुपये हो गई। यह वृद्धि दर्शाती है कि अधिक लोगों को कर कानूनों का अनुपालन करना सरल और सार्थक लगता है।

फेसलेस आईटी रिटर्न ई-असेसमेंट

2019 में लॉन्च की गई, फेसलेस ई-असेसमेंट प्रणाली ने व्यक्तियों के लिए कर जांच के तरीके को बदल दिया। इसने आमने-सामने की बैठकों को पूरी तरह से डिजिटल और गुमनाम प्रक्रिया में बदल दिया, जिससे उत्पीड़न की गुंजाइश कम हो गई और विश्वास बढ़ा है।

दिल्ली में राष्ट्रीय ई-असेसमेंट केंद्र करदाताओं और मूल्यांकन इकाइयों के लिए संपर्क का एकल बिंदु है। जब कोई आय रिटर्न चुना जाता है, तो धारा 143 (2) के तहत एक नोटिस जारी किया जाता है, और करदाता को 15 दिनों के भीतर जवाब देना होता है। फिर मामला एक स्वचालित प्रणाली के माध्यम से एक मूल्यांकन इकाई को सौंपा जाता है। करदाता को यह नहीं पता होता है कि रिटर्न का मूल्यांकन कौन कर रहा है या इसे कहाँ संभाला जा रहा है। क्षेत्रीय से गतिशील अधिकार क्षेत्र में यह बदलाव निष्पक्षता सुनिश्चित करता है और विवेकाधिकार को खत्म करता है।

मुद्रास्फीति नियंत्रण

2014 तक के वर्षों में, बढ़ती कीमतों ने मध्यम वर्ग के परिवारों को लगातार तनाव में रखा। 2009-10 और 2013-14 के बीच, मुद्रास्फीति दोहरे अंकों में रही। भोजन और ईंधन जैसी आवश्यक वस्तुएँ लगातार महंगी होती गईं। घरेलू बजट पर दबाव पड़ा और बचत करना पहुंच से बाहर हो गया। 2004-05 से 2013-14 के दशक पर नज़र डालें तो औसत वार्षिक मुद्रास्फीति 8.2 प्रतिशत पर रही। मूल्य अस्थिरता की इस लंबी अवधि ने रोजमर्रा की जिंदगी को कठिन बना दिया और भविष्य की योजना बनाना अनिश्चित हो गया।

2014 से चीजें बदलने लगीं। अगले ग्यारह सालों में महंगाई पर पूरी तरह से काबू पाया गया। 2015-16 से 2024-25 तक महंगाई औसत दर गिरकर सिर्फ़ 5 प्रतिशत रह गई। यह अंतर सिर्फ़ आंकड़ों में ही नहीं बल्कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी दिखाई देता है। स्थिर कीमतों

ने परिवारों को राहत दी। ज़रूरी चीज़ें ज़्यादा किफ़ायती हो गईं और मासिक खर्चों की योजना बनाना आसान हो गया। यह बदलाव ठोस नीति, रिजर्व बैंक के साथ मज़बूत समन्वय और बेहतर आपूर्ति-पक्ष प्रबंधन का नतीजा था। लंबे समय से बढ़ती कीमतों की मार झेल रहे मध्यम वर्ग को आखिरकार राहत मिली और अर्थव्यवस्था में उनका भरोसा फिर से लौटा।

<u>एकीकृत पेंशन योजना</u>

सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए सामाजिक सुरक्षा को मज़बूत करने के एक बड़े कदम के तौर पर, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24 अगस्त, 2024 को एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) को मंज़ूरी दी। यह योजना सेवानिवृत्ति से पहले के अंतिम 12 महीनों के दौरान प्राप्त औसत मूल वेतन के 50% के बराबर पेंशन सुनिश्चित करती है, जो कम से कम 25 साल की सेवा वाले कर्मचारियों पर लागू होती है। कम सेवा अवधि वाले लोगों के लिए, पेंशन की गणना आनुपातिक रूप से की जाएगी, जिसमें न्यूनतम योग्यता अवधि 10 वर्ष होगी। 10 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद रिटायर होने पर न्यूनतम 10,000 रुपये प्रति माह की सुनिश्चित पेंशन प्रदान की जाएगी। कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में, उनके परिवार को सुनिश्चित पेंशन के 60% के बराबर पेंशन मिलेगी। एकीकृत पेंशन योजना 1 अप्रैल, 2025 से लागू हुई और इससे लगभग 23 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों को लाभ मिलने की उम्मीद है। कई राज्य सरकारों ने भी इस मॉडल को

अपनाया है, जिससे वर्तमान में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत 90 लाख से अधिक व्यक्तियों तक इसका कवरेज बढ़ा है।

शहरी विकास और कनेक्टिविटी

पिछले ग्यारह वर्षों में, भारत के शहरी परिदृश्य में उल्लेखनीय बदलाव आया है। किफायती आवास उन लोगों तक पहुँच गया है जिन्हें इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। बेहतर सड़कें, स्वच्छ हवा, बेहतर सार्वजनिक सेवाएँ और आधुनिक परिवहन व्यवस्था के साथ शहर ज़्यादा रहने लायक बन गए हैं। मध्यम वर्ग के लिए, ये गरिमा और सुविधा लाए हैं। ये लाभ दीर्घकालिक दृष्टि, निरंतर वित्तपोषण और प्रभावी क्रियान्वयन का परिणाम हैं।

> त्वरित तथ्य:
>
> पीएमएवाई-शहरी के तहत 1.16 करोड़ घरों को मंजूरी दी गई और 92.72 लाख पूरे किए गए।
>
> स्मार्ट सिटीज की 93% परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, जिनमें 1.51 लाख करोड़ रुपये का निवेश किया गया है।
>
> भारत का मेट्रो रेल नेटवर्क बढ़कर 1,013 किलोमीटर हो गया है, जिसमें प्रतिदिन 1.12 करोड़ यात्री सफर करते हैं।

पहली बार घर खरीदने वालों से लेकर रोज़ाना मेट्रो से यात्रा करने वालों तक, करोड़ों नागरिकों ने अपने घरों, अपनी सड़कों और अपने आस-पड़ोस में बदलाव महसूस किया है।

स्मार्ट सिटीज मिशन

25 जून 2015 को शुरू किए गए स्मार्ट सिटीज मिशन ने भारतीय शहरों को एक नया जीवन दिया। इसने लोगों के रहने, घूमने, काम

करने और अपना समय बिताने के तरीके को फिर से परिभाषित किया। 2025 तक, 7545 स्वीकृत परियोजनाओं में से 93 प्रतिशत पूरी हो गई थीं, जिनका कुल निवेश 1.51 लाख करोड़ रुपये से अधिक था। 100 स्मार्ट शहरों में से प्रत्येक अब एक एकीकृत कमांड और नियंत्रण केंद्र चलाता है। ये केंद्र बेहतर सुरक्षा, यातायात नियंत्रण, अपशिष्ट संग्रह और जल प्रबंधन में सहयोग करते हैं।

83,000 से अधिक सीसीटीवी कैमरे, 1,884 आपातकालीन कॉल बॉक्स और 3,000 सार्वजनिक पता प्रणाली अब शहरों को सतर्क और उत्तरदायी रहने में मदद करती हैं। 1,200 से अधिक सार्वजनिक स्थान परियोजनाओं ने शहर के पार्कों, झील के किनारों और बाजारों में जीवन वापस ला दिया है। 2,300 सरकारी स्कूलों में 9,400 स्मार्ट कक्षाओं और 41 नई डिजिटल लाइब्रेरी के साथ शिक्षा में सुधार हुआ है। 15 शहरों में 3,100 अस्पताल के बिस्तरों और डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड पेश करने के साथ स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को भी बढ़ावा मिला। आवास के मामले में, 23 स्मार्ट शहरों ने 35,000 किफायती घर बनाए। स्मार्ट तकनीक का उपयोग करके जल आपूर्ति, ठोस अपशिष्ट और सीवरेज सिस्टम को उन्नत किया गया। 1,700 किलोमीटर स्मार्ट सड़कों, 713 किलोमीटर साइकिल लेन, 23,000 साइकिल और 1,500 से अधिक बसों को सार्वजनिक बेड़े में शामिल करने से परिवहन सुगम हो गया। 50 से अधिक शहरों ने 200 से अधिक उच्च-प्रभाव वाली परियोजनाओं को पूरा करने के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी की ओर रुख किया।

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) लाखों मध्यम-वर्ग और निम्न-आय वाले परिवारों के लिए एक मजबूत आशा बन गई है। 2015 में शुरू की गई यह योजना हर भारतीय के लिए एक सुरक्षित और सम्मानजनक घर के लक्ष्य की ओर लगातार आगे बढ़ी है। यह योजना सिर्फ़ घर बनाने तक ही सीमित नहीं है। इसने शहरों के परिवारों को गर्व, स्थिरता और सशक्तिकरण दिया है। इसका विस्तार, पहुँच और निष्पक्षता पर जोर ने इसे स्वतंत्र भारत में सबसे प्रभावशाली शहरी कल्याण योजनाओं में से एक बनाया है।

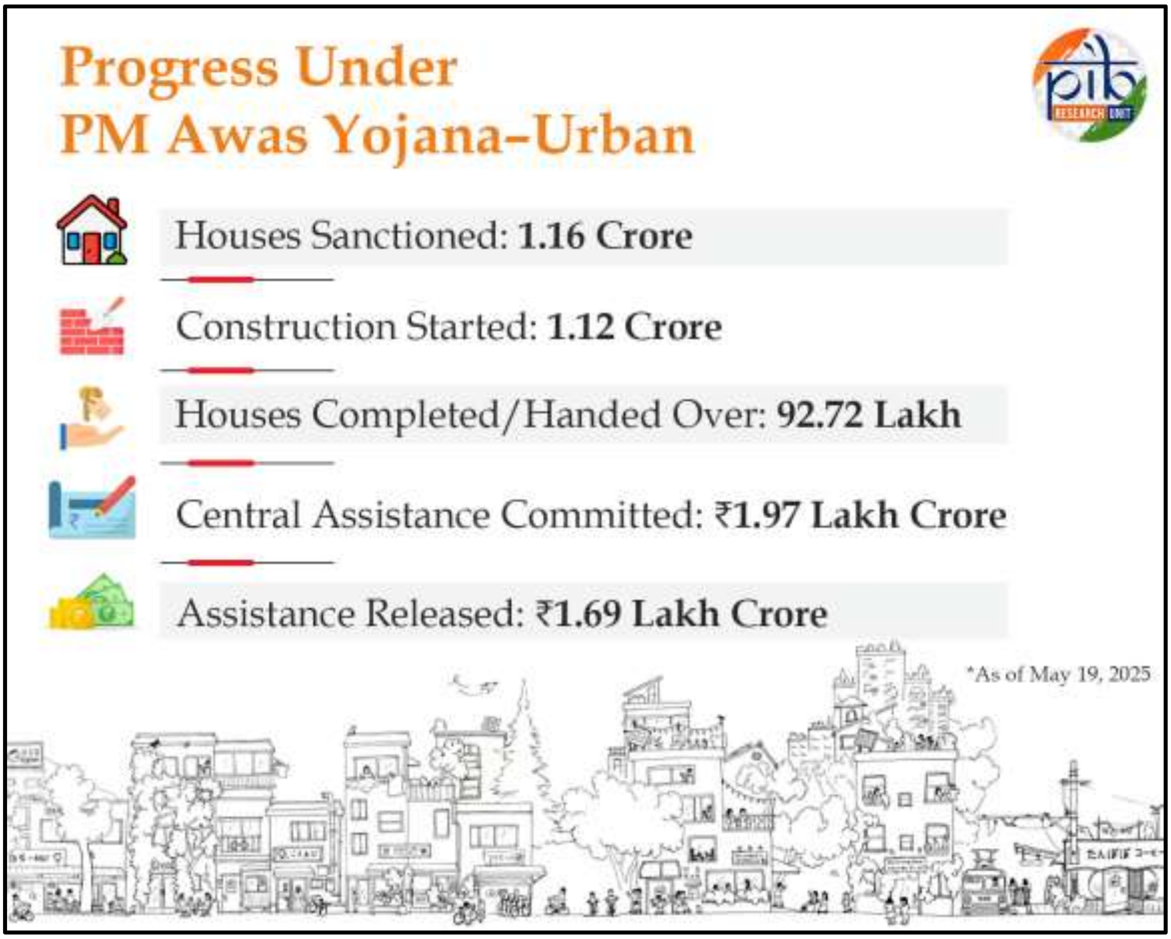

केंद्र ने सहायता के रूप में 1.97 लाख करोड़ रुपये देने का वादा किया है। इसमें से 1.69 लाख करोड़ रुपये पहले ही जारी किए जा चुके हैं।

2014 से 2025 तक, 19 मई तक, 1.16 करोड़ से ज़्यादा घरों को मंज़ूरी दी गई। 1.12 करोड़ से ज़्यादा घरों का निर्माण शुरू हो चुका है। 92.72 लाख से ज़्यादा घर बनकर तैयार हो चुके हैं या सौंपे जा चुके है। ये सिर्फ़ आँकड़े नहीं हैं, ये प्रगति की ठोस कहानियाँ हैं।

<u>मेट्रो रेल विस्तार</u>

दशकों में शहरी परिवहन में सबसे बड़ी तेज़ी देखी गई। अब 29 शहरों में मेट्रो रेल चल रही है या बन रही है। मई 2025 तक, भारत में 1,013 किलोमीटर मेट्रो लाइन परिचालन में थी, जो 2014 में सिर्फ़ 248 किलोमीटर थी। यानी सिर्फ़ ग्यारह साल में 763 किलोमीटर का इज़ाफ़ा। कुल मेट्रो रेल नेटवर्क के मामले में भारत अब दुनिया भर में तीसरे स्थान पर है।

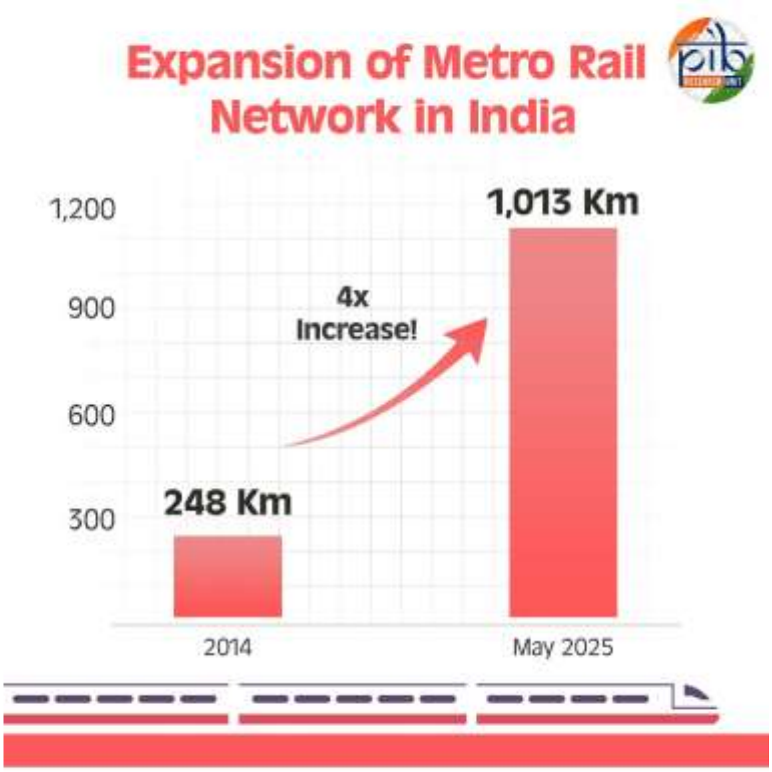

इस अवधि में 992 किलोमीटर की 34 मेट्रो परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। 2013-14 में प्रतिदिन 28 लाख यात्रियों की संख्या अब 1.12 करोड़ को पार कर गई है। नई लाइनें चालू करने की गति नौ गुना बढ़ गई है। औसतन अब हर महीने 6 किलोमीटर मेट्रो लाइनें चालू हो रही हैं, जबकि 2014 से पहले यह आंकड़ा सिर्फ 0.68 किलोमीटर प्रति महीने था। मेट्रो रेल के लिए वार्षिक बजट भी छह गुना से अधिक बढ़ गया है, जो 2013-14 में 5,798 करोड़ से बढ़कर 2025-26 में 34,807 करोड़ रुपये हो गया है।

<u>उड़ान योजना</u>

21 अक्टूबर 2016 को शुरू की गई उड़े देश का आम नागरिक (उड़ान) योजना ने आम नागरिकों के लिए हवाई यात्रा को सस्ता और सुलभ बना दिया है। अपने छठे वर्ष में, उड़ान ने 625 मार्गों के माध्यम से 2 जल हवाई अड्डों और 15 हेलीपोर्ट सहित 90 हवाई अड्डों को जोड़ा है। 27 अप्रैल 2017 को शिमला से दिल्ली के लिए पहली उड़ान भरी गई। तब से, 1.49 करोड़ से अधिक यात्रियों को कम लागत वाली क्षेत्रीय हवाई यात्रा का लाभ मिला है। भारत का हवाई अड्डा नेटवर्क 2014 में 74 हवाई अड्डों से बढ़कर 2024 में 159 हो गया है। वंचित क्षेत्रों में हवाई संपर्क का समर्थन करने के लिए व्यवहार्यता अंतर निधि के रूप में 4,023.37 करोड़ रुपये वितरित किए गए हैं। इस योजना ने पर्यटन को बढ़ावा दिया है, स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच में सुधार किया है और टियर 2 और टियर 3 शहरों में

व्यापार को बढ़ावा दिया है, जिससे समावेशी क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा मिला है।

<u>रियल एस्टेट विनियमन</u>

घर खरीदने वालों के हितों की रक्षा करने और आवास क्षेत्र में पारदर्शिता लाने के लिए, संसद ने 2016 में रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम पारित किया। यह रियल एस्टेट लेनदेन में जवाबदेही की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। आरईआरए के तहत, प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने एक नियामक प्राधिकरण स्थापित किया, जिसे पंजीकृत विकास के लिए परियोजना विवरण सूचीबद्ध करने वाले सार्वजनिक पोर्टल को बनाए रखने का काम सौंपा गया।

17 मार्च, 2025 तक, पूरे भारत में रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरणों द्वारा 1.4 लाख से अधिक उपभोक्ता शिकायतों का समाधान किया गया है। यह दर्शाता है कि कैसे कानून ने रियल एस्टेट बाजार में विश्वास बहाल करने और निष्पक्ष व्यवहार सुनिश्चित करने में मदद की है।

स्वास्थ्य सेवा की सुलभता और वहनीयता

भारत में स्वास्थ्य सेवा ने पिछले ग्यारह वर्षों में एक मौन लेकिन दूरगामी बदलाव देखा है। लक्षित सार्वजनिक योजनाओं और डिजिटल पहुंच के मिश्रण के माध्यम से, सरकार ने लाखों लोगों, खासकर मध्यम वर्ग के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा को किफायती और सुलभ बनाया है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए मुफ़्त अस्पताल में

भर्ती से लेकर देश भर में उपलब्ध कम कीमत वाली दवाओं तक, आज लोगों के पास अपने स्वास्थ्य खर्चों पर बेहतर नियंत्रण है। इन योजनाओं का समर्थन करने वाली डिजिटल रीढ़ ने नामांकन, पहुँच और ट्रैकिंग को पहले से कहीं ज़्यादा आसान बना दिया है। इस बदलाव ने मध्यम वर्ग को नौकरशाही की बाधाओं के बिना दवाओं पर बचत, समय पर उपचार और चिकित्सा सुरक्षा का लाभ उठाने का अवसर दिया है।

> त्वरित तथ्य:
>
> 40.84+ करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी किए गए, जिससे 8.59 करोड़ से अधिक लोग अस्पताल में भर्ती हुए।
>
> जन औषधि केंद्रों की संख्या 80 से बढ़कर 16,290 हो गई, जिससे ₹38,000 करोड़ की बचत हुई।
>
> आयुष्मान भारत का विस्तार 70+ आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए किया गया

आयुष्मान भारत: सुरक्षा जाल का विस्तार

आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक रूप से वित्तपोषित स्वास्थ्य आश्वासन योजनाओं में से एक बनकर उभरी है। 3 मई, 2025 तक, 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 40.84 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं। इस योजना ने 1,19,858 करोड़ रुपये मूल्य के 8.59 करोड़ लोगों को अस्पताल में भर्ती होने में सक्षम बनाया है, जिससे परिवारों को कर्ज में डाले बिना माध्यमिक और तृतीयक देखभाल तक पहुँच सुनिश्चित हुई है।

31,916 सूचीबद्ध अस्पतालों का एक नेटवर्क सुविधा को और बढ़ाता है। 29 अक्टूबर 2024 को, इस योजना का 70 और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए, चाहे उनकी आय कुछ भी हो विस्तार किया गया है। यह विस्तार बुजुर्ग मध्यम वर्ग के लिए स्वास्थ्य सेवा के वित्तीय बोझ को कम करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

जन औषधि: दवाओं को किफ़ायती बनाना

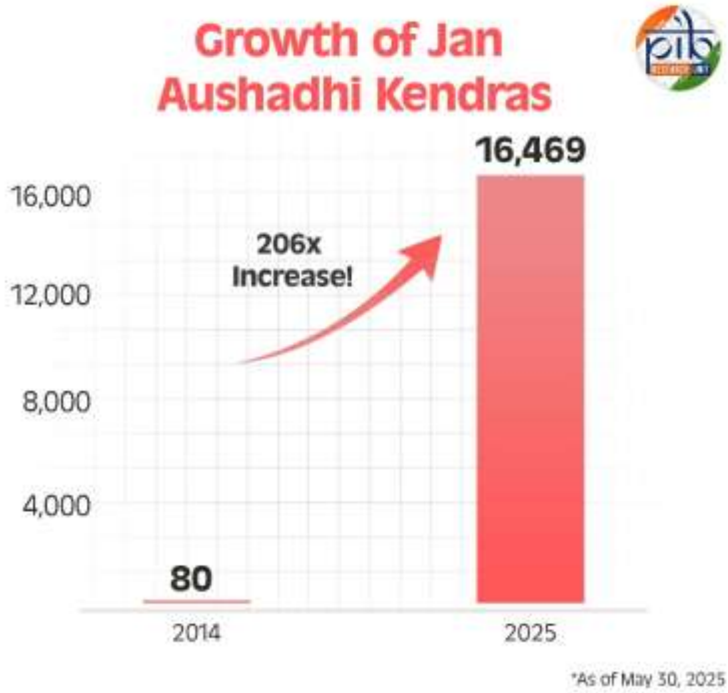

प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना (पीएमबीजेपी) ने ज़रूरी दवाओं को आम नागरिक की पहुँच में ला दिया है। 20 मई, 2025 तक जन औषधि केंद्रों की संख्या 2014 में सिर्फ़ 80 से बढ़कर 16,469 हो गई थी। ये आउटलेट ब्रांडेड विकल्पों की तुलना में 50 से 80 प्रतिशत कम कीमत पर दवाइयाँ देते हैं, साथ ही डब्ल्यूएचओ प्रमाणित आपूर्तिकर्ताओं के ज़रिए सख्त गुणवत्ता मानकों को सुनिश्चित किया जाता है।

यह योजना प्रतिदिन लगभग 10 से 12 लाख लोगों को सेवा प्रदान करती है, और पिछले ग्यारह वर्षों में संचयी बचत 38,000 करोड़ रुपये से अधिक होने का अनुमान है। मधुमेह या हृदय रोग जैसी पुरानी बीमारियों का इलाज करने वाले मध्यम वर्ग के लिए, इसने वास्तविक और स्थायी राहत दी है। उत्पाद श्रेणी में अब 2,110 दवाइयाँ और 315 सर्जिकल उत्पाद शामिल हैं, जो सभी प्रमुख उपचारों को कवर करते हैं। लाखों परिवारों, विशेष रूप से मध्यम वर्ग के लिए, इस योजना का मतलब कम वित्तीय तनाव और अधिक मानसिक शांति है।

शिक्षा और कौशल विकास

पिछले ग्यारह वर्षों में, सरकार ने भारत के महत्वाकांक्षी मध्यम वर्ग के लिए कौशल और सीखने के परिदृश्य को फिर से परिभाषित किया है। रोजगार, समावेशिता और उद्योग संरेखण पर स्पष्ट ध्यान देने के साथ, कार्यक्रमों के एक विस्तृत नेटवर्क ने लाखों भारतीयों को नौकरी के लिए कौशल हासिल करने में मदद की है। 2014 में स्थापित कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने इस यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक महत्वपूर्ण जरूरत के जवाब के रूप में जो शुरू हुआ वह आज दुनिया में सबसे बड़े मानव पूंजी विकास प्रयासों में से एक बन गया है। अल्पकालिक पाठ्यक्रमों से लेकर प्रशिक्षुता, सामुदायिक शिक्षा से लेकर उद्यमिता तक, सरकार के दृष्टिकोण ने शहरी केंद्रों और ग्रामीण परिवारों को समान रूप से छुआ है, जिससे अवसर, स्थिरता और आशा मिली है।

त्वरित तथ्य:

पीएमकेवीवाई ने महिलाओं और हाशिए पर पड़े समूहों सहित 1.63 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित किया।

एनएपीएस ने 2016 से अब तक 40 लाख प्रशिक्षुओं को सीधे वजीफा भुगतान के साथ रखा है।

आईटीआई 9,977 से बढ़कर 14,615 हो गए, नामांकन बढ़कर 14 लाख हो गए।

<u>प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई)</u>

2015 में शुरू की गई, पीएमकेवीवाई भारत में अल्पकालिक कौशल प्रशिक्षण की रीढ़ बन गई। 18 अप्रैल, 2025 तक, इसने विनिर्माण, स्वास्थ्य सेवा, आईटी और निर्माण जैसे क्षेत्रों में प्रमाणित प्रशिक्षण के माध्यम से 1.63 करोड़ से अधिक युवाओं को व्यावहारिक कौशल से

लैस किया। इस योजना में समावेशिता पर जोर दिया गया, जिससे महिलाओं और हाशिए पर पड़े समुदायों की बड़ी भागीदारी देखी गई। यह समय के साथ विकसित भी हुआ, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मेचैट्रॉनिक्स जैसे भविष्य के डोमेन पेश किए गए। पीएमकेवीवाई ने सुनिश्चित किया कि कौशल प्रशिक्षण एक विशेषाधिकार नहीं बल्कि, अधिकार है, जिसे दूरदराज के गांवों में भी उपलब्ध कराया गया है। पीएमकेवीवाई के तहत प्रशिक्षित कुल उम्मीदवार

[illegible]	
[illegible]	[illegible]
[illegible] 1.0 (2015-16)	19,86,016
[illegible] 2.0 (2016-20)	1,10,00,816
[illegible] 3.0 (2020-22)	7,37,502
[illegible] 4.0 (2022-26)*	26,01,224
[illegible]	**1,63,25,558**

18 अप्रैल 2025 तक के आँकड़े

* - पीएमकेवीवाई 4.0 को लागू किया जा रहा है

राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस)

एनएपीएस के तहत प्रशिक्षुता के पुनरुद्धार ने लाखों युवा भारतीयों के लिए 'कमाते हुए सीखना' को एक वास्तविकता बना दिया है। 2016

से 40 लाख से अधिक प्रशिक्षुओं को उद्योगों में रखा गया है, और मासिक वजीफा सीधे उनके खातों में जमा किया जाता है। इस योजना ने कक्षा में सीखने और कार्यस्थल की अपेक्षाओं के बीच की खाई को पाटने में मदद की। इसने नियोक्ताओं को प्रशिक्षित प्रतिभाओं की एक अनवरत आपूर्ति भी दी, जिससे भारत का औद्योगिक आधार ज़मीन से ऊपर तक मज़बूत हुआ।

आईटीआई पारिस्थितिकी तंत्र का आधुनिकीकरण

भारत के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान लंबे समय से व्यावसायिक शिक्षा का एक स्तंभ रहे हैं। पिछले एक दशक में, इन संस्थानों में एक बड़ा विस्तार और उन्नयन हुआ। 2014 में आईटीआई की संख्या लगभग 9,977 से बढ़कर 2024 में 14,615 से अधिक हो गई। इसमें देश भर में 4,638 नए संस्थानों को शामिल करना शामिल है, जिससे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में तकनीकी प्रशिक्षण तक पहुँच में सुधार हुआ है। इसी अवधि के दौरान नामांकन 9.5 लाख से बढ़कर 14 लाख से अधिक हो गया, जो युवाओं और उनके परिवारों के बीच व्यावसायिक शिक्षा में बढ़ते भरोसे को दर्शाता है।

व्यावसायिक प्रशिक्षण को और मज़बूत करने के एक और बड़े कदम में, मई 2025 में, सरकार ने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान उन्नयन के लिए राष्ट्रीय योजना और कौशल विकास के लिए पाँच राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना को मंज़ूरी दी। यह केन्द्र प्रायोजित योजना 60,000 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ कार्यान्वित की जाएगी, जिसमें केन्द्र, राज्य और उद्योग का योगदान शामिल होगा।

डिजिटल गवर्नेंस और सुविधा

पिछले ग्यारह वर्षों में, भारत में डिजिटल गवर्नेंस मध्यम वर्ग के सशक्तिकरण का एक मजबूत स्तंभ बनकर उभरा है। सुलभ, कुशल और पारदर्शी डिजिटल सेवाओं की ओर सरकार के केंद्रित प्रयास ने नागरिकों के राज्य के साथ बातचीत करने के तरीके को बदल दिया है। दस्तावेज़ों तक पहुँच से लेकर सेवा वितरण तक, वित्तीय समावेशन से लेकर कल्याण तक पहुँच में, डिजिटल उपकरणों ने लालफीताशाही को कम किया है, समय की बचत की है और घरों को सुविधाजनक बनाया है। मध्यम वर्ग को, विशेष रूप से, जल्दी सेवाओं के मिलने, कार्यालयों के कम चक्कर लगाने और कम कागजी कार्रवाई से लाभ हुआ है। आधार, डिजिलॉकर और उमंग जैसी प्रमुख पहलों ने न केवल सार्वजनिक सेवाओं को मोबाइल और कागज़ रहित बनाया है, बल्कि सरकारी प्रणालियों में विश्वास भी बढ़ाया है।

तथ्य एक नजर में:

अप्रैल 2025 तक 141.88 करोड़ आधार आईडी जारी किए गए ।

डिजिलॉकर 52.51 करोड़ उपयोगकर्ताओं को सेवाएं प्रदान करता है, जिसके तहत अब तक 914.19 करोड़ से अधिक डिजिटल दस्तावेज जारी किए गए हैं।

उमंग ऐप के 8.13 करोड़ उपयोगकर्ता हैं और 2,297 सेवाएं हैं, जिसमें 591 करोड़ लेनदेन होते हैं।

आधार: एक विश्वसनीय डिजिटल पहचान

2009 में शुरू किया गया आधार दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पहचान कार्यक्रम बन गया है। मार्च 2014

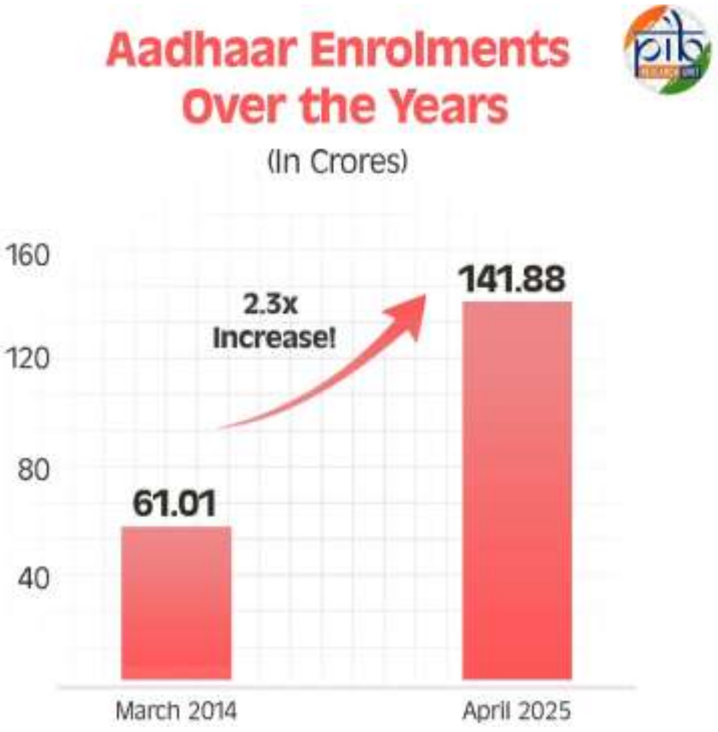

तक 61.01 करोड़ आधार नंबर जारी किए जा चुके थे, जो अप्रैल 2025 के अंत तक बढ़कर 141.88 करोड़ से ज़्यादा हो गए। अब तक आधार ने 150 बिलियन से ज़्यादा प्रमाणीकरण लेन-देन को सक्षम बनाया है। इसका डिज़ाइन सुनिश्चित करता है कि लाभ डुप्लिकेट और धोखाधड़ी को हटाकर इच्छित प्राप्तकर्ताओं तक पहुँचें।

मध्यम वर्ग ने बैंकिंग, पेंशन, स्कूल में दाखिले और ऑनलाइन सेवाओं तक आसान पहुँच देखी है, जो सभी सहज आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से संभव हुआ है। इसका बढ़ता उपयोग एक सुरक्षित और विश्वसनीय डिजिटल पहचान प्रणाली में जनता के भरोसे को दर्शाता है।

<u>डिजिलॉकर: मांग पर दस्तावेज़</u>

1 जुलाई, 2015 को लॉन्च किया गया डिजिलॉकर डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत एक प्रमुख पहल है। यह एक डिजिटल दस्तावेज़ वॉलेट प्रदान करता है जो नागरिकों को अपने फ़ोन या डेस्कटॉप से

प्रामाणिक दस्तावेज़ों तक पहुँचने, संग्रहित करने और साझा करने की अनुमति देता है। फरवरी 2017 से कानूनी रूप से मूल कागजात के बराबर माने जाने वाले डिजिलॉकर ने भौतिक प्रतियों को साथ रखने या जमा करने की आवश्यकता को कम कर दिया है।

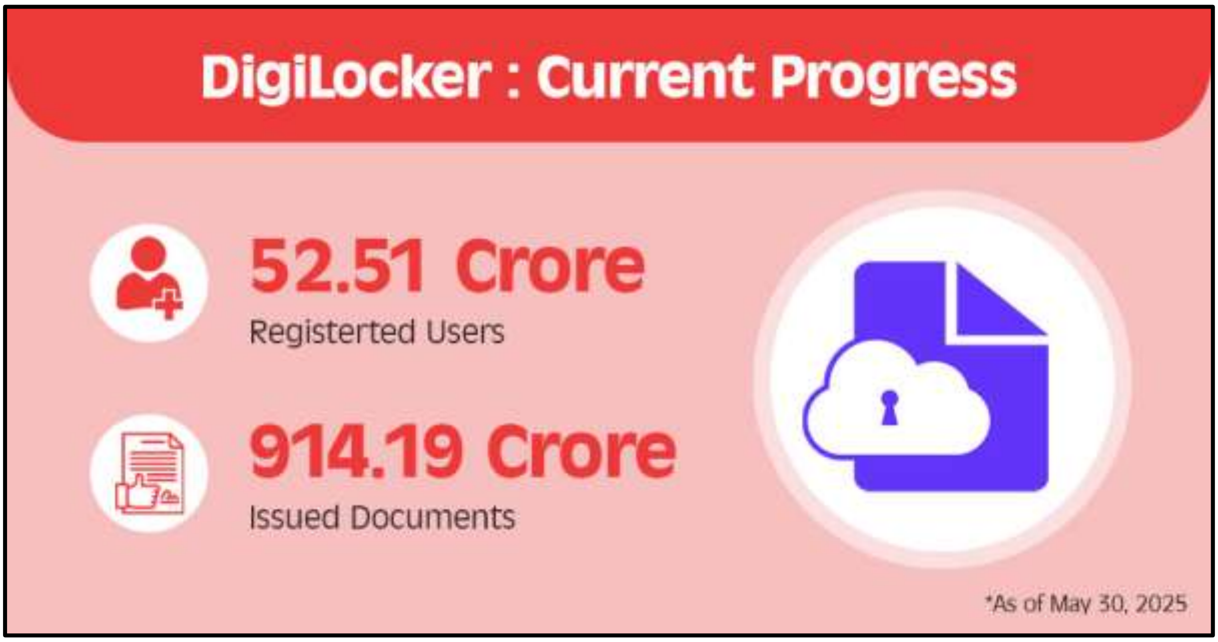

20 मई, 2025 तक, 52.19 करोड़ से अधिक उपयोगकर्ताओं ने साइन अप किया था, जिसमें 1,936 संस्थानों द्वारा 914.19 करोड़ से अधिक दस्तावेज जारी किए गए थे। मध्यम वर्ग के लिए, इसका मतलब है स्कूल प्रमाणपत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड और बहुत कुछ तक आसान पहुँच - कभी भी, कहीं भी।

<u>उमंग ऐप: प्लेटफ़ॉर्म एक सेवाएँ अनेक,</u>

2017 में लॉन्च किए गए उमंग ऐप ने शासन को वास्तव में मोबाइल बना दिया है। यह केंद्र, राज्य और स्थानीय निकायों की सेवाओं तक

पहुँचने के लिए एक एकीकृत प्लेटफ़ॉर्म प्रदान करता है। बिलों का भुगतान करने से लेकर वैक्सीन अपॉइंटमेंट बुक करने तक, उमंग सरकार को नागरिकों के करीब लाता है। 2017 में सिर्फ़ 0.25 लाख उपयोगकर्ताओं और 166 सेवाओं से शुरू हुआ यह ऐप अब मई 2025 तक 8.13 करोड़ से ज़्यादा उपयोगकर्ताओं और 209 विभागों में 2,297 सेवाओं तक पहुँच गया है। ऐप ने 591.63 करोड़ से ज़्यादा लेन-देन की सुविधा भी दी है। मध्यम वर्ग के लिए, इस ऐप का मतलब है कम कतारें, ज़्यादा नियंत्रण और सार्वजनिक सेवाओं तक जल्दी पहुँच।

निष्कर्ष

पिछले ग्यारह वर्षों में, सरकार ने सार्थक तरीकों से मध्यम वर्ग के उत्थान के लिए अटूट प्रतिबद्धता दिखाई है। शुरू की गई नीतियों और सुधारों ने न केवल रोज़मर्रा की चुनौतियों को कम किया है, बल्कि वित्तीय सुरक्षा, आवास, स्वास्थ्य सेवा और कौशल विकास को भी मज़बूत किया है। ये बदलाव भारत की विकास कहानी में मध्यम वर्ग की महत्वपूर्ण भूमिका की स्पष्ट समझ को दर्शाते हैं। निष्पक्षता, सरलता और पहुँच पर ध्यान केंद्रित करके, सरकार ने सुनिश्चित किया है कि लाखों मध्यम आय वाले परिवार भविष्य का सामना आत्मविश्वास के साथ करने के लिए बेहतर ढंग से सुसज्जित हों। इस निरंतर और विचारशील दृष्टिकोण ने जीवन को बदल दिया है और निरंतर प्रगति के लिए एक मजबूत नींव रखी है।

- □□□□□://□□□.□□□.□□□.□□/□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□.□□□□?□□□□=2098352
- □□□□□://□□□.□□□.□□□.□□/□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□.□□□□?□□□□=1601463
- □□□□□://□□□.□□□.□□□.□□/□□□□□□□□□□□□□□□□.□□□□?□□□□=1971680
- □□□□□://□□□□□□□□.□□/□□□□□□□/□□□□□□□□□□□□□□□□□/□□□□□/184/□□946_□□□4□□.□□□?□□□□□□=□□□□□
- □□□□□://□□□.□□□.□□□.□□/□□□□□□□□□□□□□□□□.□□□□?□□□□=1643289
- □□□□□://□□□.□□□.□□□.□□/□□□□□□□□□□□□□□□□.□□□□?□□□□=2114325
- □□□□□://□□□.□□□.□□□.□□/□□□□□□□□□□□□□□□□.□□□□?□□□□=2127416
- □□□□□://□□□.□□□.□□□.□□/□□□□□□□□□□□□□□□□.□□□□?□□□□=2067940
- □□□□□://□□□.□□□.□□□.□□/□□□□□□□□□□□□□□□□.□□□□?□□□□=2129121
- □□□□□://□□□.□□□□□□.□□□.□□/□□□□□□□/
- □□□□□://□□□.□□□.□□□.□□/□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□.□□□□?□□□□=2098487
- □□□□□://□□□.□□□□□□□□□□□□□□.□□□.□□/
- □□□□□://□□□□□□□□□.□□□□□□.□□□.□□/□□□/#/

- □□□□□://□□□□.□□□□.□□□□.□□/□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□.□□□□□?□□□□=2098352
- □□□□□://□□□□□□□□□□□□□□□□□.□□□□.□□/
- □□□□□://□□□□.□□□□.□□□□.□□/□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□.□□□□□?□□□□□□□=153202&□□□□□□□□□□□□=3
- □□□□□://□□□□.□□□□.□□□□.□□/□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□.□□□□□?□□□□□=2122148

□□□□□□□□□□□ 04/ □□□□□□□ □□ 11 □□□□□ □□ □□□□□□□□□□□□